(b) ICICI has entered into a Memorandum of Understanding with Moregan Guaranty International Finance Corporation (MGIFC), a subsidiary of J.P. Morgan, USA. MFIFC will participate in the equity of ICICI Asset Management Company Ltd. to the extent of 40% and also provide technical know-how and support services for ICICI Mutual Fund.

आयकर की बकाया धनराशि

2774. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरौला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1994 को आयकर तथा अन्य केन्द्रीय करों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धन-राशि बकाया थी;

(ख) उक्त तारीख को प्रत्येक केन्द्रीय कर से संबंधित कितने मामले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार न्यायालयों में लंबित थे; और

(ग) इन करों की बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Non-Implementation of the Recommendations of the Third and Fourth Pay Commissions

2775. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the matters which have been agreed to in principle by Government, on the basis of the Reports of the Third and Fourth Central Pay Commissions, but on which the decision has not been taken so far have again been referred to the Fifth Pay Commission;

(b) if so, the details thereof;

(c) if answer to part (a) above, be in the negative, by when the decision on the recommendations of the Fourth Pay Commission is proposed to be taken; and

(d) by when the decision agreed to in principle will be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (d) All the accepted recommendations of the Third & Fourth Pay Commissions have been implemented except the recommendations in para 19.8 and para 10.263 (part) of the Report of the Fourth Pay Commission relating to the age of super-annuation for Scientific and Technical Personnel and uniformity in grant of special pay to the personnel in various Trades in the CPOs respectively. These two recommendations are under consideration.

गैर-विकासात्मक व्यय

2776. **श्री आस मोहम्मद:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में गैर-विकासात्मक व्यय में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस विक्षोभकारी प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया है; और

(ग) यदि हां, तो गैर-विकासात्मक व्यय में हो रही अक्षुण्ण वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, नहीं। गैर-विकासात्मक श्रेणी में व्यय की अनिवार्य और अन्य अत्यावश्यक मदों जैसे ब्याज संदाय, रक्षा, पुलिस, पेंशन आदि को छोड़कर अन्य गैर-विकासात्मक व्यय में पिछले तीन वर्षों में वास्तविक रूप से गिरावट आई है, जिसे नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है:—